

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 26-04-2025

### विषय सूची

मार्च-अप्रैल 2025 में वज्रपात/विदूत विसर्जन से 160 से अधिक लोगों की मृत्यु

विश्व बैंक: भारत की अत्यधिक गरीबी घटकर 2.3% रह गई

LRS के अंतर्गत भारतीयों द्वारा विदेशों में भेजी जाने वाली धनराशि में 29% की कमी आई

भारत में चिकित्सा पर्यटन

कृषि भूमि विषाक्त भारी धातु प्रदूषण से दूषित

एल्गोरिद्म प्रबंधन

DRDO की सफलता: भारत ने हाइपरसोनिक प्रोपल्शन को आगे बढ़ाया

### संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय शून्य खसरा-रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26

बिहार मुख्यमंत्री विदूत उपभोक्ता सहायता योजना

विकसित वाइब्रेट विलेजेज कार्यक्रम

इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन का निधन

नियंत्रण रेखा (LoC)

भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य: महुआडांड

कस्तूरी मृग

केजी सुरेश इंडिया हैबिटेड सेंटर के निदेशक नियुक्त

## मार्च-अप्रैल 2025 में वज्रपात/विद्युत विसर्जन से 160 से अधिक लोगों की मृत्यु

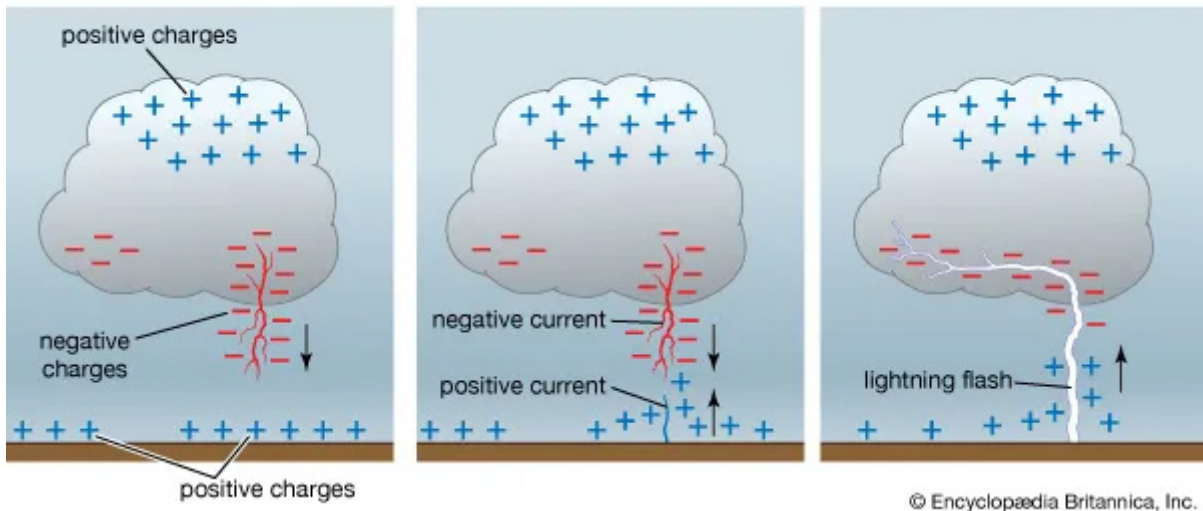
### संदर्भ

- मार्च 2025 से अप्रैल 2025 के मध्य तक 12 भारतीय राज्यों में वज्रपात/विद्युत विसर्जन से लगभग 162 लोगों की मृत्यु हो गयी।
- बिहार में 99 मौतें (राष्ट्रीय कुल आँकड़ों का 61%) दर्ज की गईं, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है।

### वज्रपात/विद्युत विसर्जन क्या है?

- वज्रपात/विद्युत विसर्जन बादल और धरातल में आवेशित कणों के बीच एक विद्युत निर्वहन है।
- हालाँकि वायु सामान्यतः एक विद्युत इन्सुलेटर के रूप में कार्य करती है, जब वोल्टेज लगभग 3 मिलियन वोल्ट प्रति मीटर (V/m) तक पहुँच जाता है, तो वायु के इन्सुलेटिंग गुण टूट जाते हैं, जिससे एक शक्तिशाली विद्युत प्रवाह गुजरता है।
- इसके परिणामस्वरूप अचानक ऊर्जा निकलती है, जिससे एक प्रज्वलित चमक और संबंधित ध्वनि तरंग (गर्जन) उत्पन्न होती है।

### How lightning develops



### भारत में वज्रपात/विद्युत विसर्जन की बढ़ती घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारक

- भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियाँ:** पूर्वी राज्यों और तटीय क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता के कारण वहाँ गर्जन और वज्रपात/विद्युत विसर्जन की घटनाएँ अधिक होती हैं।
  - हिमालय और पश्चिमी घाट जैसी स्थलाकृति भी वज्रपात/विद्युत विसर्जन की आवृत्ति को प्रभावित करती है।
- मानसून की गतिशीलता:** मानसून के दौरान होने वाली तीव्र वर्षा और संवहनी गतिविधियाँ भारत में विद्युत विसर्जन का प्रमुख कारण हैं।
  - नमी से भरपूर वायुराशि का अभिसरण और मानसून के दौरान उष्ण, आर्द्र वायु का ऊपर उठना प्रायः गरज और विद्युत विसर्जन का कारण बनता है।
- शहरीकरण और औद्योगीकरण:** तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण से वातावरण में कृत्रिम गर्मी स्रोतों और एरोसोल की संख्या बढ़ जाती है।
  - ये संवहन को बढ़ाते हैं और गरज के साथ अधिक बार आँधी-तूफान उत्पन्न करते हैं, जिससे विद्युत विसर्जन की घटनाएँ बढ़ती हैं।
- जलवायु परिवर्तन:** वैश्विक जलवायु पैटर्न में बदलाव स्थानीय मौसम पर प्रभाव डाल रहे हैं।
  - बढ़ते तापमान और आर्द्रता स्तर में परिवर्तन तूफान की गतिशीलता को बदलते हैं, जिससे विद्युत विसर्जन की घटनाएँ अधिक बार और तीव्र हो सकती हैं।

- **कृषि संबंधी गतिविधियाँ:** कृषि अवशेषों का जलाना और वनों की कटाई वातावरण में कणों के संचय में योगदान करते हैं।
  - ये कण बादलों के निर्माण को प्रभावित करते हैं और गरज के साथ विद्युत विसर्जन की संभावना बढ़ाते हैं।

### सरकारी पहल

- **CROPC** (जलवायु प्रतिरोधकता अवलोकन प्रणाली संवर्धन परिषद) ने भारत की पहली *विद्युत विसर्जन पूर्व चेतावनी प्रणाली* विकसित की है, जिसका उद्देश्य विद्युत विसर्जन गिरने की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना और अलर्ट जारी करना है।
- **सचेत मोबाइल ऐप** को लोगों को आसन्न विद्युत विसर्जन खतरों के बारे में सचेत करने के लिए लॉन्च किया गया।
  - **2020 में, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM)-पुणे ने दामिनी ऐप** विकसित किया।

### आगे का राह

- संचार प्रणाली को मजबूत करना ताकि चेतावनी प्रभावी ढंग से संवेदनशील जनसंख्या तक पहुँचे।
- स्थानीय अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- मानसून और पूर्व-मानसून मौसम के दौरान बिजली सुरक्षा उपायों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना।
- **NDMA** के प्रोटोकॉल का बुनियादी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ताकि जानमाल की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

Source: DTE

## विश्व बैंक: भारत की अत्यधिक गरीबी घटकर 2.3% रह गई

### संदर्भ

- विश्व बैंक के गरीबी और समानता संक्षिप्त विवरण (PEBs) के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 16% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गई, जो गरीबी उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।

## MEASURING STANDARDS

Poverty at different lines 2022-23  
poverty rate (%)

International poverty line (\$2.15/day)	2.3
Lower middle-income class poverty line (\$3.65/day)	28.1
Multidimensional poverty measure	15.5

Source: World Bank

### गरीबी और समानता संक्षिप्त विवरण (PEBs) के बारे में

- ये विश्व बैंक द्वारा जारी द्वि-वार्षिक रिपोर्टें हैं, जो 100 से अधिक विकासशील देशों में गरीबी, असमानता और साझा समृद्धि की प्रवृत्तियों का त्वरित अवलोकन प्रदान करती हैं। यह विश्व बैंक और IMF की स्प्रिंग और वार्षिक बैठकों के दौरान प्रकाशित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य वैश्विक एजेंडे में गरीबी उन्मूलन को प्रमुख बनाए रखना है।

### मापन

- गरीबी दर और गरीबी रेखा के अनुसार कुल गरीबों की संख्या, जिसमें राष्ट्रीय गरीबी रेखा, अंतर्राष्ट्रीय अत्यधिक गरीबी रेखा (\$2.15, 2017 PPP), निम्न-मध्यम-आय (\$3.65) और उच्च-मध्यम-आय (\$6.85) गरीबी रेखाएँ शामिल हैं।
- समय और देशों के बीच तुलनात्मक गरीबी और असमानता प्रवृत्तियाँ ताकि समान मानकों के आधार पर निष्पक्ष तुलना की जा सके।
- बहुआयामी गरीबी माप, जिसमें गरीबी के ऐसे पहलू शामिल हैं जो केवल आय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच जैसी गैर-आर्थिक वंचनाओं को भी दर्शाते हैं।
- असमानता की गणना गिनी इंडेक्स (Gini Index) द्वारा की जाती है।



### भारत के हालिया निष्कर्ष

- भारत ने गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें अत्यधिक गरीबी—जिसे क्रय शक्ति समता (PPP) शर्तों पर प्रति दिन \$2.15 के आधार पर मापा जाता है—2011-12 में 16% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गई है।
- इस गिरावट से 171 मिलियन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सहायता मिली।
- ग्रामीण अत्यधिक गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% हो गई, जबकि शहरी गरीबी 10.7% से 1.1% तक पहुँच गई, जिससे ग्रामीण-शहरी असमानता अत्यधिक कम हुई।
- \$3.65/दिन निम्न-मध्यम-आय (LMIC) देशों की गरीबी रेखा का उपयोग करके, गरीबी 61.8% से घटकर 28.1% हो गई, जिससे 378 मिलियन लोग इस सीमा से ऊपर उठे।
- विश्व बैंक के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI), जिसमें अत्यधिक गरीबी शामिल है लेकिन पोषण और स्वास्थ्य की वंचना शामिल नहीं है, ने दिखाया कि गैर-आर्थिक गरीबी 2005-06 में 53.8% से घटकर 2019-21 में 16.4% और 2022-23 में 15.5% हो गई।
- भारत के पाँच सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य—उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश—2022-23 में देश की 54% अत्यधिक गरीब जनसंख्या और 2019-21 में 51% बहुआयामी गरीब का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - 2011-12 में, इन राज्यों का योगदान 65% अत्यधिक गरीबों का था, लेकिन 2022-23 तक इन्हीं राज्यों ने दो-तिहाई समग्र कमी को बढ़ावा दिया।
- वेतन असमानता और बेरोजगारी
  - सुधार के बावजूद, वेतन असमानता अधिक बनी हुई है—शीर्ष 10% जनसंख्या निचले 10% की

तुलना में 13 गुना अधिक कमाती है।

- खपत आधारित गिनी सूचकांक में सुधार हुआ (28.8 से 25.5 तक), लेकिन आय असमानता बढ़ी (गिनी 52 से बढ़कर 62 हो गया)।
- युवा बेरोजगारी दर 13.3% है, जबकि स्नातकों के बीच यह 29% तक पहुँच गई है। अधिकांश नौकरियाँ अनौपचारिक बनी हुई हैं, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में।
- महिला रोजगार दर 31% है, और पुरुषों की तुलना में 234 मिलियन का अंतर बना हुआ है, हालाँकि 2021-22 के बाद से समग्र रोजगार बढ़ रहा है।

#### क्या आप जानते हैं ?

- गिनी सूचकांक जनसंख्या के अन्दर आय असमानता का एक माप है, जो 0 से 1 तक होता है, जहाँ 0 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है और 1 पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है।

Source :BS

### LRS के अंतर्गत भारतीयों द्वारा विदेशों में भेजी जाने वाली धनराशि में 29% की कमी आई

#### संदर्भ

- भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत भारतीय निवासियों द्वारा विदेशों में प्रेषित धनराशि, जनवरी के 2,768.89 मिलियन डॉलर से 29% घटकर फरवरी 2025 में 1,964.21 मिलियन डॉलर रह गई।

#### उदारीकृत धन प्रेषण योजना (LRS)

- एलआरएस विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का हिस्सा है, जो भारत से बाहर जाने वाले धन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
- इस योजना के अंतर्गत, नाबालिगों सहित निवासी व्यक्ति, स्वीकार्य चालू या पूँजी खाता लेनदेन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेज सकते हैं।

- इन लेन-देन में शिक्षा, विदेश में चिकित्सा उपचार, संपत्ति की खरीद और विदेशी शेयरों में निवेश शामिल हैं।
- फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट ने एलआरएस लेनदेन पर स्रोत पर कर एकत्रित एकत्र करने की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया।
- इस बदलाव से यात्रा और विदेशी मुद्रा क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना थी, जिससे आउटबाउंड पर्यटन, शिक्षा और एयरलाइन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

### गिरावट के कारण:

- विदेशी विश्वविद्यालयों में जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या शीर्ष तीन गंतव्य देशों - कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके में एक साथ घटी है।
- डेटा से पता चलता है कि 2024 में इन प्रमुख गंतव्यों पर अध्ययन परमिट प्राप्त करने वाले कम से कम 25% भारतीय छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है।
- इस अवधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजारों में उतार-चढ़ाव का सामना करने के कारण काफी संख्या में लोगों ने अपनी यात्रा योजनाओं को छोड़ दिया या स्थगित कर दिया।

### प्रेषण

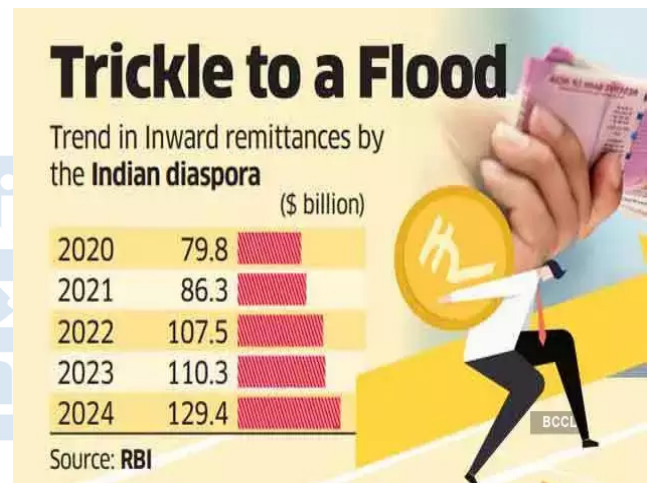
- धन प्रेषण, दूसरे देश में लोगों, प्रायः परिवार के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने का एक तरीका है।
- सामान्यतः विदेशी देशों में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा भेजा जाता है, विशेषतः वे जो ब्लू-कॉलर या कुशल नौकरियों में कार्यरत हैं।
- **प्रभाव:** धन प्रेषण कई देशों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो उनकी आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करता है, और कभी-कभी राष्ट्रीय व्यापार घाटे को वित्तपोषित करने में सहायता करता है।
- **स्थानांतरण के तरीके:** धन प्रेषण बैंकों, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजा जा सकता है।

### प्रेषण के दो प्रकार

- लेन-देन के उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के प्रेषण होते हैं: आवक प्रेषण और जावक प्रेषण।
- **आवक प्रेषण:** आवक प्रेषण शब्द का अर्थ है घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खाते से दूसरे खाते में धन का हस्तांतरण।
- **जावक प्रेषण:** देश से बाहर या विदेश में धन के हस्तांतरण को जावक प्रेषण कहा जाता है।

### भारत का धन प्रेषण

- भारत का धन प्रेषण 2010-11 में 55.6 बिलियन डॉलर से दोगुना होकर 2023-24 में 118.7 बिलियन डॉलर हो गया है।



- **यू.एस. और यू.के. का योगदान:** यू.एस. और यू.के. से प्राप्त धन वित्त वर्ष 24 में कुल आवक धन का लगभग दोगुना होकर 40% हो गया, जो वित्त वर्ष 17 में 26% था।
- **यू.एस. अग्रणी योगदानकर्ता:** यू.एस. वित्त वर्ष 21 में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत बन गया, जिसने 23.4% का योगदान दिया। यह वित्त वर्ष 24 में बढ़कर लगभग 28% हो गया।
- **UAE की भूमिका:** UAE अभी भी दूसरा सबसे बड़ा धन प्रेषण स्रोत है, जो 19.2% का योगदान देता है, जिसमें भारतीय प्रवासी निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और पर्यटन जैसी ब्लू-कॉलर नौकरियों में हैं।

- **सिंगापुर की बढ़ती हिस्सेदारी:** सिंगापुर की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 24 में 6.6% तक पहुँच गई, जो वित्त वर्ष 17 में 5.5% थी, जो तब से इसका उच्चतम हिस्सा है।
- **राज्यवार वितरण:** आधे धन प्रेषण महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु गए। हरियाणा, गुजरात और पंजाब जैसे अन्य राज्यों में यह हिस्सेदारी कम (5% से कम) थी।
- **प्रेषण का आकार:** 5 लाख रुपये से अधिक के प्रेषण कुल प्रेषण का 28.6% था, जबकि 40.6% प्रेषण 16,500 रुपये या उससे कम थे।

Source: IE

## भारत में चिकित्सा पर्यटन

### संदर्भ

- आयुष राज्य मंत्री ने कहा कि भारत अब उपचार और चिकित्सा पर्यटन के लिए सबसे अधिक माँग वाले स्थलों में से एक के रूप में उभरा है।

### परिचय

- चिकित्सा पर्यटन से तात्पर्य चिकित्सा उपचार, प्रक्रियाओं या स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए किसी दूसरे देश या क्षेत्र की यात्रा करने की प्रथा से है।
- भारत में चिकित्सा पर्यटन उद्योग का मूल्य लगभग 9 बिलियन डॉलर है, देश कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी और अंग प्रत्यारोपण में उन्नत उपचार के लिए विश्व भर से रोगियों को आकर्षित करता है।
- भारत में चिकित्सा पर्यटन 2023 में साल-दर-साल लगभग 33% बढ़कर लगभग 6.6 लाख हो गया।
- भारत में चिकित्सा पर्यटन के लिए लोकप्रिय स्थलों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलूर और हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं, जो प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमुख केंद्र हैं।

### भारत में चिकित्सा पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार कारक

- **लागत प्रभावी उपचार:** भारत में अमेरिका या यूरोप जैसे देशों की तुलना में चिकित्सा प्रक्रियाएँ बहुत कम लागत पर उपलब्ध हैं।

### COST ANALYSIS OF MAJOR TREATMENTS IN INDIA COMPARED TO EMERGING NATIONS OF MEDICAL TOURISM (IN LAKH)

#### HEART BYPASS



#### HEART VALVE REPLACEMENT



- **उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा:** भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अस्पतालों और कुशल चिकित्सा पेशेवरों के साथ एक अच्छी तरह से स्थापित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचा है।
- **उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता:** भारतीय अस्पताल अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक उपचारों से सुसज्जित हैं, विशेष रूप से कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स जैसे क्षेत्रों में।
- **कम प्रतीक्षा समय:** चिकित्सा पर्यटक समय पर उपचार प्राप्त कर सकते हैं, प्रायः कुछ पश्चिमी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में आम लंबे प्रतीक्षा समय से बचते हैं।
- **सरकारी सहायता और नीतियाँ:** भारत सरकार ने ऐसी नीतियाँ लागू की हैं जो चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहित करती हैं, जिसमें चिकित्सा वीजा सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को बढ़ावा देना शामिल है।

### भारत के लिए महत्त्व

- **आर्थिक विकास:** यह अंतर्राष्ट्रीय रोगियों से राजस्व उत्पन्न करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य

सेवा क्षेत्र और संबंधित उद्योगों (जैसे, आतिथ्य, परिवहन) में योगदान देता है।

- **सुधारित स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना:** चिकित्सा पर्यटकों की सेवा करने के लिए, अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं में निवेश करते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता में सुधार करके स्थानीय रोगियों को भी लाभान्वित करते हैं।
- **भारत की वैश्विक छवि को बढ़ावा देना:** यह वैश्विक स्वास्थ्य सेवा गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, चिकित्सा क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश और भागीदारी को आकर्षित करता है।
- **तकनीकी उन्नति:** उन्नत उपचार और देखभाल के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की माँग भारतीय स्वास्थ्य सेवा में नवाचार और नई चिकित्सा तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देती है।
- **कौशल विकास:** यह अत्यधिक कुशल कार्यबल के विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विविध रोगी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
- **राजनयिक संबंध:** जैसे-जैसे विभिन्न देशों के रोगी भारत में उपचार चाहते हैं, वे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य से परिचित होते हैं।
  - अनुभवों का यह आदान-प्रदान राष्ट्रों के बीच बेहतर समझ और सद्भावना को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मजबूत राजनयिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त होता है।

### चुनौतियाँ

- मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर से कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- अधिकांश चिकित्सा देखभाल बीमा द्वारा कवर नहीं की जाती है और यह चिकित्सा मूल्य यात्रा (MVT) को कम आकर्षक बनाता है।
- MVT सुविधाकर्ता अच्छी तरह से संगठित और मान्यता प्राप्त नहीं हैं। कई गैर-पेशेवर एजेंट चिकित्सा मूल्य यात्रियों का शोषण करते हैं।
- **नियमों का अभाव:** MVT क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यापक नियम नहीं हैं, जो इस क्षेत्र को

असंगठित बनाता है और सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी का अभाव है।

- **MVT का प्रचार:** व्यक्तिगत अस्पताल अपना प्रचार कर रहे हैं लेकिन भारत को चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए कोई प्रभावी अभियान नहीं है।
- **मान्यता:** हालाँकि, भारत राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (NABH) के लिए मान्यता बोर्ड के माध्यम से एक मजबूत मान्यता प्रणाली बनाए रखता है। हालाँकि, विदेशी देशों में एनएबीएच के बारे में बहुत अधिक जागरूकता नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मरीज अभी भी संयुक्त आयोग अंतर्राष्ट्रीय (JCI) मान्यता को बहुत अधिक महत्व देते हैं।

### आगे की राह

- तेज रफ़्तार आधुनिक जीवनशैली के साथ, स्वास्थ्य और वैकल्पिक उपचारों की माँग बढ़ रही है।
- भारत ने आयुष में भारी निवेश किया है और आयुष के ज़रिए उपचार और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा मूल्य वाले यात्रियों को आकर्षित करने की अद्वितीय स्थिति में है।
- भारत को चिकित्सा मूल्य यात्रा गंतव्य के रूप में विनियमित करने, सुविधा प्रदान करने और विपणन करने के लिए सरकार से अधिक समर्थन की आवश्यकता है।

Source: AIR

### कृषि भूमि विषाक्त भारी धातु प्रदूषण से दूषित

#### संदर्भ

- एक नए अध्ययन से पता चला है कि विषैली भारी धातुओं और उपधातुओं से होने वाला मृदा प्रदूषण, संपूर्ण विश्व में फसलों की उपज को अत्यधिक कम कर रहा है और खाद्य आपूर्ति को दूषित कर रहा है।

#### मुख्य विशेषताएँ

- शोध में पाया गया कि विश्व की 14 से 17 प्रतिशत कृषि मृदा (लगभग 242 मिलियन हेक्टेयर) कम से कम एक खतरनाक धातु के लिए सुरक्षित सीमा से अधिक है।



- यह संदूषण उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले अनुमानित 900 मिलियन से 1.4 बिलियन लोगों को प्रभावित करता है।
- दक्षिणी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिणी चीन जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए, निम्न-अक्षांश यूरेशिया में एक अत्यधिक दूषित क्षेत्र की पहचान की गई है।
- व्यापक संदूषक कैडमियम, आर्सेनिक, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम हैं।

### भारी धातु संचय के कारण

- **मानवजनित कारण:** खनन, प्रगलन, औद्योगिक गतिविधियाँ और गहन कृषि (अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग)।
- **प्राकृतिक कारण:** धातु-समृद्ध आधारशिला और कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा जो प्रदूषक संचय को सुविधाजनक बनाती है।

### धातु संदूषण का प्रभाव

- **खाद्य शृंखला संदूषण:** प्रदूषित मृदा में उगाई जाने वाली फसलें कैडमियम, आर्सेनिक, सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं को अवशोषित करती हैं। ये धातुएँ भोजन के सेवन के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करती हैं।
- **जैव संचय:** कम खुराक के लंबे समय तक सेवन से जैव संचय हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप तंत्रिका संबंधी और विकास संबंधी विकार सहित पुरानी बीमारियाँ हो सकती हैं।
- **जैव विविधता की हानि:** जहरीली धातुएँ केंचुओं, कीड़ों और सूक्ष्म जीवों जैसे लाभकारी जीवों को हानि पहुँचाती हैं, जिससे मृदा के नीचे और ऊपर दोनों जगह जैव विविधता कम हो जाती है।
- **भूमि क्षरण:** निरंतर प्रदूषण मृदा को बंजर बनाता है, जिससे भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण में योगदान होता है।

### चिंताएँ

- **डेटा अंतराल:** उप-सहारा अफ्रीका, उत्तरी रूस और मध्य भारत के कुछ हिस्सों से सीमित जानकारी का मतलब यह हो सकता है कि यह मुद्दा और भी व्यापक है।

- **खाद्य व्यापार जोखिम:** वैश्विक खाद्य व्यापार संदूषण को कम जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर सकता है, जिससे व्यापक खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
- **धातुओं की बढ़ती माँग:** बढ़ती औद्योगिक माँग के कारण तत्काल शमन उपायों के बिना संदूषण संकट अधिक खराब हो सकता है।

### मृदा संरक्षण के लिए सरकारी पहल

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:** यह किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए मृदा की पोषक स्थिति रिपोर्ट प्रदान करती है।
- **जैविक खेती को बढ़ावा:** परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) जैसी पहल मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करती है।
- **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA):** यह एकीकृत कृषि प्रणालियों और कृषि वानिकी प्रथाओं के माध्यम से मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

### वैश्विक पहल

- **वैश्विक मृदा भागीदारी :** यह वैश्विक मृदा शासन में सुधार और स्थायी मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एफएओ के नेतृत्व वाली पहल है।
- **संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए सम्मेलन :** यह भूमि क्षरण को रोकने और वैश्विक स्तर पर स्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।
  - इसने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता के लिए प्रतिज्ञा की है।
- **4 प्रति 1000 पहल:** इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मृदा कार्बन स्टॉक को सालाना 0.4% बढ़ाना है।

### आगे की राह

- क्षेत्रीय मृदा स्वास्थ्य वेधशालाएँ स्थापित करें और मृदा सर्वेक्षणों के कवरेज का विस्तार करना।



- **फाइटोरेमेडिएशन:** दूषित मृदा को साफ करने के लिए हाइपरएक्यूमुलेटर पौधों और सूक्ष्मजीवों का उपयोग।
- **सर्कुलर इकोनॉमी:** मृदा के प्रदूषण को रोकने के लिए ई-अपशिष्ट, औद्योगिक कचरे का पुनर्चक्रण और प्रबंधन।
- **किसान जागरूकता कार्यक्रम:** किसानों को भारी धातु के जोखिम, सुरक्षित कृषि पद्धतियों और वैकल्पिक फसल प्रणालियों के बारे में शिक्षित करना।

Source: DTE

## एल्गोरिद्म प्रबंधन

### संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और यूरोपीय आयोग द्वारा 2024 के संयुक्त अध्ययन में कार्य संगठन और रोजगार की गुणवत्ता पर एल्गोरिथमिक प्रबंधन (AM) प्रौद्योगिकियों के प्रभावों की जाँच की गई।

### एल्गोरिथमिक प्रबंधन (AM) प्रौद्योगिकियाँ

- **AM की परिभाषा:** AM (एल्गोरिथमिक प्रबंधन) में डेटा संग्रह, निगरानी, वास्तविक समय निर्णय लेने और मीट्रिक-संचालित मूल्यांकन का उपयोग करके कार्यों एवं कार्यकर्ता प्रदर्शन को आवंटित करना, निगरानी करना और मूल्यांकन करना शामिल है।
  - यह बड़े डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, जियोलोकेशन और पहचान योग्य उपकरणों जैसी डिजिटल तकनीकों को एकीकृत करता है।
- **AM का अनुप्रयोग:** मूल रूप से डिजिटल श्रम प्लेटफार्मों पर प्रमुख, AM अब गोदामों, कारखानों, कॉल सेंटर, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और निर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में फैल गया है।

### निष्कर्ष

- **सकारात्मक प्रभाव:** फ्रांस और इटली में, AM प्रौद्योगिकियों ने रोजगार की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से हानि पहुँचाए बिना कार्य संगठन में सुधार किया।

- **नकारात्मक प्रभाव:** दक्षिण अफ्रीका और भारत में, AM प्रौद्योगिकियों ने रोजगार की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बना।
- **भारत-विशिष्ट निष्कर्ष:** भारत में केवल 16% दूरस्थ/ऑनलाइन श्रमिकों के पास एक समर्पित कार्यस्थान है।
  - कई दूरस्थ श्रमिकों के पास उचित कार्यस्थान सेटअप नहीं है, जिससे निम्न जोखिम बढ़ जाते हैं: मस्क्युलोस्केलेटल विकार (जैसे, पीठ के निचले हिस्से और गर्दन में दर्द), आँखों में तनाव और थकान।
    - लंबे समय तक बैठे रहने के कारण मोटापा, मधुमेह और हृदय संबंधी रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याएँ।

### कार्यस्थलों में एल्गोरिथमिक प्रबंधन को देश किस प्रकार विनियमित कर रहे हैं

- चीन और नीदरलैंड ने कार्यस्थल एल्गोरिथम में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर बल देने वाले नियम पेश किए हैं।
- स्पेन ने वर्कर्स स्टैच्यूट एक्ट में संशोधन किया है, जिसके तहत नियोक्ताओं को काम करने की स्थितियों को प्रभावित करने वाले एल्गोरिथमिक मापदंडों का खुलासा करना आवश्यक है।
- अमेरिका में, एल्गोरिथमिक जवाबदेही अधिनियम व्यक्तिगत डेटा को संभालने या स्वचालित निर्णय लेने वाले उच्च जोखिम वाले AI और मशीन लर्निंग सिस्टम के आकलन को अनिवार्य बनाता है।

Source: BS

## DRDO की सफलता: भारत ने हाइपरसोनिक प्रोपल्शन को आगे बढ़ाया

### संदर्भ

- DRDO के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशाला DRDL ने एक्टिव-कूल्ड स्ट्रैमजेट सबस्केल कॉम्बस्टर का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया।
  - यह भारत में हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

### हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी के बारे में

- यह एक अत्याधुनिक क्षेत्र है जो वाहनों को मैक 5 (ध्वनि की गति से पाँच गुना) से अधिक गति से चलने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है।

#### Mach Number (M)

- It is the ratio of speed of object and speed of sound.
  - Subsonic:  $M < 1$
  - Transonic:  $M = 0$  (Speed of an object is equal to the speed of sound)
  - Supersonic:  $1 < M < 3$
  - High Supersonic:  $3 < M < 5$
  - Hypersonic:  $M > 5$
- The Space Shuttle re-enters the atmosphere at high hypersonic speeds ( $M \sim 25$ ).

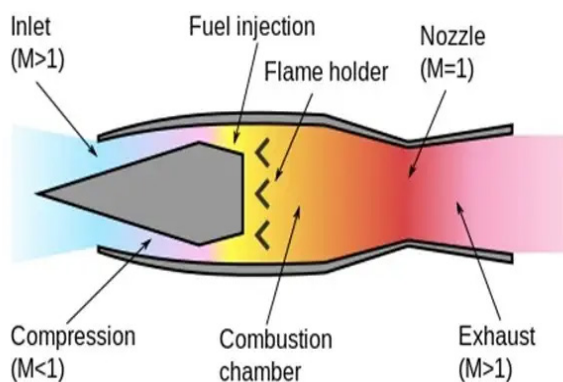
- इसका उपयोग मुख्यतः हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और उन्नत एयरोस्पेस प्रणालियों में किया जाता है।

### हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी की मुख्य विशेषताएँ

- वायु-श्वास इंजन:** हाइपरसोनिक वाहन स्क्रेमजेट (सुपरसोनिक दहन रैमजेट) इंजन का उपयोग करते हैं, जो ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइज़र ले जाने के बजाय दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं।
  - यह उन्हें निरंतर उच्च गति वाली उड़ान के लिए अधिक कुशल बनाता है।

### स्क्रेमजेट (सुपरसोनिक दहन रैमजेट) इंजन

- स्क्रेमजेट एक वायु-श्वास इंजन है, जो वायु के सुपरसोनिक दहन द्वारा हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है।



### रैमजेट से मुख्य अंतर:

- रैमजेट में, दहन से पहले वायु धीमी होकर सबसोनिक गति पर आ जाती है।
- स्क्रेमजेट में, पूरी प्रक्रिया के दौरान वायु सुपरसोनिक रहती है, जिससे गति बढ़ जाती है।
- कार्य सिद्धांत:** किसी भी घूर्णनशील कंप्रेसर के बिना आने वाली वायु को संपीड़ित करने के लिए वाहन की आगे की गति का उपयोग करता है।
- भारत स्क्रेमजेट इंजन के उड़ान परीक्षण का प्रदर्शन करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया।

### स्क्रेमजेट इंजन परीक्षण का महत्त्व

- लंबी अवधि के सुपरसोनिक दहन की पुष्टि:** यह परीक्षण स्क्रेमजेट दहनक के डिजाइन और दक्षता की पुष्टि करता है, जिससे निरंतर उच्च गति वाली उड़ान क्षमता सुनिश्चित होती है।
  - यह जनवरी में किए गए 120 सेकंड के पहले के परीक्षण के बाद है, जिसमें वृद्धिशील प्रगति का प्रदर्शन किया गया है।
- भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत करना:** स्क्रेमजेट इंजन वायु में सांस लेने की क्षमता को सक्षम करते हैं, जिससे ऑनबोर्ड ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होती है और मिसाइल की रेंज बढ़ती है।
  - सफल परीक्षण हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पूर्ण पैमाने पर उड़ान परीक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है।

Source: News On AIR

## संक्षिप्त समाचार

### राष्ट्रीय शून्य खसरा-रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26

#### संदर्भ

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय शून्य खसरा-रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का शुभारंभ किया।

### खसरा

- खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करती है।
- यह संक्रमित व्यक्ति के नाक, मुँह या गले से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैलता है।
- सामान्यतः संक्रमण के 10-12 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें तेज बुखार, नाक बहना, आँखों में लालिमा और मुँह के अंदर छोटे-छोटे सफ़ेद धब्बे शामिल हैं।

### रूबेला

- रूबेला एक तीव्र, सामान्यतः हल्का एक्सेंथेमेटस बुखार है जो दुनिया भर में अतिसंवेदनशील बच्चों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है।
  - इसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है।
- **लक्षण:** हल्का बुखार, गले में खराश और चेहरे पर दाने निकलना।

### भारतीय परिदृश्य

- भारत प्रत्येक जिले में एमआर वैक्सीन की दो खुराक के साथ 95% से अधिक टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- 2024 में, देश में खसरा और रूबेला के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जिसमें 2023 की तुलना में खसरा में 73% और रूबेला में 17% की गिरावट आई।
- **यू-विन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म:** इसका उद्देश्य ऑनलाइन पंजीकरण, अपॉइंटमेंट बुकिंग और डिजिटल प्रमाणन की पेशकश करके टीकाकरण सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है।

Source: AIR

## बिहार मुख्यमंत्री विदुत उपभोक्ता सहायता योजना

### समाचार में

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना

के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में ₹15,995 करोड़ मंजूर किए।

- यह राशि पिछले वर्ष के आवंटन से ₹652 करोड़ अधिक है।

### मुख्यमंत्री विदुत उपभोक्ता सहायता योजना

- इसे बिहार में पर्याप्त बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार को कम करना और पूरे राज्य में बिजली की समान पहुँच को बढ़ावा देना था।
- सब्सिडी का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट लागत को कम करना है, और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से सीधे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को प्रदान किया जाएगा।
- यह सब्सिडी उपभोक्ताओं के मासिक ऊर्जा बिलों में दिखाई देगी और अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे उच्च विद्युत शुल्क दरों को ऑफसेट करने में मदद मिलेगी।

### क्या आप जनते हैं?

- भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA) प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है।

Source :TH

## विकसित वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम

### संदर्भ

- विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के लिए पंजीकरण आधिकारिक तौर पर MY भारत पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ हुआ।

### विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के बारे में

- सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की एक संयुक्त पहल, विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम, 15 से 30 मई

2025 तक लेह-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा।

- युवा मामले और खेल मंत्रालय की अगुवाई में, गृह मंत्रालय के समन्वय में, कार्यक्रम को स्थानीय शासन निकायों और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के समर्थन से लागू किया जाएगा।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **युवा-नेतृत्व विकास:** 100 चयनित गाँवों में समुदायों के साथ सीधे काम करने के लिए देश भर से कुल 500 MY भारत स्वयंसेवकों को जुटाया जाएगा।
    - केंद्र शासित प्रदेशों से 10 और भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य से 15 MY भारत स्वयंसेवकों का चयन किया जाएगा।
  - **सहभागिता का दायरा:** स्वयंसेवक निम्न पहलों के माध्यम से बुनियादी स्तर पर विकास को आगे बढ़ाएँगे-
    - सामुदायिक सहभागिता, युवा नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक संवर्धन, स्वास्थ्य सेवा जागरूकता और सहायता, कौशल निर्माण और शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण सर्वोत्तम अभ्यास, कैरियर परामर्श सत्र, फिटनेस गतिविधियाँ (खेल, योग, ध्यान), और माई ड्रीम इंडिया पर ओपन माइक, निबंध, फायरसाइड चैट आदि।
- **रणनीतिक महत्व:**
  - कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गाँवों के “मानचित्र पर अंतिम” होने की लंबे समय से चली आ रही धारणा को समाप्त करना है। इसके बजाय, यह उन्हें 2047 तक विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा में ‘पहले गाँव’ के रूप में मनाना चाहता है।
  - युवा नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी और रणनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देकर, विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत् विकास और राष्ट्रीय एकीकरण की नींव रखने की उम्मीद है।

## इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन का निधन

### समाचार में

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन का बेंगलुरु में निधन हो गया।

### डॉ. के. कस्तूरीरंगन के बारे में

- उनका जन्म 24 अक्टूबर, 1940 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था।
- उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से भौतिकी में बीएससी (ऑनर्स) और एमएससी की डिग्री हासिल की।
- उन्होंने 1971 में अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में प्रायोगिक उच्च ऊर्जा खगोल विज्ञान में पीएचडी पूरी की।
- उन्होंने अपना करियर एक्स-रे खगोलशास्त्री के रूप में प्रारंभ किया और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया।

### प्रमुख योगदान

- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - उन्होंने 1994 से 2003 तक इसरो के पाँचवें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
  - उन्होंने इसरो सैटेलाइट सेंटर का निर्देशन किया और भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्यक्रम की स्थापना की।
  - उन्होंने नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट-2) और भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट (IRS-1A और 1B) के साथ-साथ वैज्ञानिक उपग्रहों के विकास से संबंधित गतिविधियों की देखरेख की।
  - उन्होंने भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास में योगदान दिया।
- **शिक्षा और नीति:** उन्होंने पश्चिमी घाट और राष्ट्रीय



शिक्षा नीति जैसी कई महत्वपूर्ण समितियों का नेतृत्व किया।

- उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- वे राज्यसभा के सदस्य (2003-2009) थे और भारत के योजना आयोग से जुड़े थे।
- **पुरस्कार और सम्मान:** विज्ञान और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

Source : TH

## नियंत्रण रेखा (LoC)

### सन्दर्भ

- भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा सहित जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की घटनाओं की सूचना दी है।

### परिचय

- LoC पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और भारत के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की पहचान करने के लिए बिंदुओं का सीमांकन करती है।
- LoC 1972 के शिमला समझौते के बाद अस्तित्व में आई और यह द्विपक्षीय रूप से सहमत सैन्य रेखा है, न कि कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सीमा।
- वर्तमान LoC की उत्पत्ति 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद स्थापित पहली युद्ध विराम रेखा से पता लगाई जा सकती है, जो 1948 तक चली।
  - 1949 में, संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा की गई, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच 1949 के कराची समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें उन बिंदुओं का सीमांकन किया गया जो जम्मू और कश्मीर में दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा को परिभाषित करेंगे।

Source: TH

## भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य: महुआडांड

### समाचार में

- झारखंड के महुआडांड भेड़िया अभयारण्य में हाल ही में किए गए एक अध्ययन में आदिवासी सांस्कृतिक प्रथाओं और भेड़ियों के मांस बनाने के व्यवहार के बीच संबंधों का पता लगाया गया है।

### महुआडांड भेड़िया अभयारण्य

- यह झारखंड में स्थित है और 1976 में पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर लुप्तप्राय भारतीय ग्रे वुल्फ के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था।
  - इस अभयारण्य के निर्माण का श्रेय मुख्य रूप से भारतीय वन सेवा के अधिकारी एस.पी. शाही को जाता है, जिन्होंने भेड़ियों के संरक्षण के लिए खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व का समर्थन किया था।
  - इसमें असमतल घास के मैदान, घने जंगल और पहाड़ियाँ हैं और यह तेंदुए, भालू, लकड़बग्घा, सियार, हिरण और कई पक्षी प्रजातियों सहित विभिन्न वन्यजीवों के लिए एक विविध आवास प्रदान करता है।
  - यह भारत का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है जो भारतीय ग्रे वुल्फ को समर्पित है।

### ग्रे वुल्फ (कैनिस ल्यूप्स)

- यह कभी उत्तरी अमेरिका से लेकर भारत तक उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता था।
- आज, उनकी सीमा अधिक सीमित है, मुख्य रूप से कनाडा, अलास्का, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के दूरदराज के जंगली क्षेत्रों में।
- यह प्रजाति CITES परिशिष्ट II में शामिल है, भूटान, भारत, नेपाल और पाकिस्तान की आबादी को छोड़कर, जिन्हें परिशिष्ट I में सूचीबद्ध किया गया है।
- इसे IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

**क्या आप जानते हैं?**

- भारतीय भेड़िया (कैनिस ल्यूप्स पैलिप्स) ग्रे वुल्फ की एक उप-प्रजाति है जो अर्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में निवास करती है।
- यह मुख्य रूप से झाड़ियों, घास के मैदानों और अर्ध-शुष्क चरागाह पारिस्थितिकी तंत्रों में निवास करता है।
- ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों सहित पूर्वी क्षेत्रों में, वे नम, कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- इसे भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत रखा गया है।

Source :DTE

**कस्तूरी मृग****संदर्भ**

- कस्तूरी मृग के प्रजनन के प्रयास 1965 में प्रारंभ हुए, लेकिन भारत में अब इस प्रजाति के संस्थापक मृग भी नहीं हैं।

**परिचय**

- **स्वरूप:** रात या गोधूलि के समय सक्रिय रहने वाले छोटे, अकेले खुर वाले जानवर, मोस्चिडे कुल से संबंधित।



- **निवास स्थान:** वे मुख्य रूप से हिमालय पर्वतों में 2,500 से 5,000 मीटर की ऊँचाई पर रहते हैं।
  - वे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जा सकते हैं।
- **प्रजातियाँ:** भारत में, मुख्य प्रजाति कश्मीर कस्तूरी मृग (मोशस क्यूप्रियस) है, अन्य प्रजातियाँ हिमालयी कस्तूरी

मृग (मोशस ल्यूकोगैस्टर) हैं जो विभिन्न हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

- कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है।
- **कस्तूरी:** नर अपने पेट के पास एक ग्रंथि से एक विशेष कस्तूरी का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग वे क्षेत्र को चिह्नित करने और साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं।
  - यह कस्तूरी इत्र उद्योग और पारंपरिक चिकित्सा में बेहद मूल्यवान है, जो उन्हें अवैध शिकार का लक्ष्य बनाती है।
- **खतरे:** निवास स्थान की क्षति, कस्तूरी के लिए अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन उनके अस्तित्व को खतरे में डालते हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:** इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा 'लुप्तप्राय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।

Source: DTE

**के जी सुरेश इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक नियुक्त****संदर्भ**

- इंडिया हैबिटेट सेंटर (IHC) ने प्रोफेसर केजी सुरेश को अपना नया निदेशक नियुक्त किया है।

**इंडिया हैबिटेट सेंटर (IHC)**

- इंडिया हैबिटेट सेंटर की स्थापना 1993 में की गई थी।
- इसकी स्थापना विभिन्न आवास और पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को एक साथ लाने के लिए की गई थी।
- **वास्तुकार:** प्रसिद्ध वास्तुकार जोसेफ एलन स्टीन ने आईएचसी का डिजाइन तैयार किया था, जो अपने पर्यावरण के अनुकूल और लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई वास्तुकला के लिए जाना जाता है।
- **उद्देश्य:**

- ♦ जल, वायु, शोर और अपशिष्ट प्रदूषण, ऊर्जा और इसके संरक्षण, जल और मानव अपशिष्ट प्रबंधन और ऐसे अन्य मामलों सहित आवास से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- ♦ आवास, मानव बस्तियों और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी का दस्तावेजीकरण करना।
- ♦ आवास और मानव बस्तियों और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना।
- ♦ केंद्र के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग और समन्वय करना।

**Source: IE**

